भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4836

दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

अनुसंधान संविदायें

4836. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आपके मंत्रालय के अंतर्गत परामर्शदाताओं, एनजीओ, शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों को दी गई अनुसंधान संविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसंधान संविदाएं प्रदर्शित की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संविदाएं प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (घ): रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा परामर्शदाताओं, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों को कोई अनुसंधान संविदाएं नहीं दी गई हैं। तथापि, इस विभाग ने पेट्रोरसायन क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना स्कीम (सीओई) के तहत पॉलिमर के क्षेत्र में काम कर रहे शैक्षिक उत्कृष्टता या अनुसंधान के सिद्ध ट्रेक रिकार्ड वाले उन मौजूदा प्रतिष्ठित शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को पिछले 3 वर्षों में 3 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान दिया है जिनके पास **https://chemicals.nic.in/schemes.** पर प्रदर्शित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्कीम के लिए यथा-अनुमोदित स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त/सक्षम जनशक्ति/अनुसंधान कर्मचारियों सहित यथोचित आधारभूत ढांचा और मुख्य अनुसंधान कर्मचारी हैं। अनुमोदित उत्कृष्टता केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:

1) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) - लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलिमेरिक मटेरियल (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर में "बायो-इंजीनियर्ड सस्टेनेबल पॉलिमर

सिस्टम्स" में उत्कृष्टता केन्द्र। उत्कृष्टता केन्द्र की कुल अनुमोदित लागत 10.0272 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5 करोड़ रुपये भारत सरकार से, 4.16 करोड़ रुपये सिपेट से और 0.85 करोड़ रुपये उद्योग भागीदारों से प्राप्त होंगे।

2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की में "प्रोसेस डेवलपमेंट वेस्टवॉटर मैनेजमेंट इन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज" में उत्कृष्टता केन्द्र; जिसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 13.16 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4.40 करोड़ रुपये भारत सरकार का योगदान होगा, संस्थान से 3.01 करोड़ रुपये और उद्योग भागीदार से 5.75 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

3) नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे में "स्पेशलिटी पॉलिमर फॉर कस्टमाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग" में उत्कृष्टता केन्द्र जिसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 5.60 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.80 करोड़ रुपये भारत सरकार का योगदान होगा और शेष 2.80 करोड़ रुपये की राशि संस्थान की होगी।

*****